क्र०सं०	वस्तुएं	आयात (करोड़ रु० में)	
		1988-89	1989-90
5.	अखबारी कागज	196.70	223.67
6.	अलौह धातुएं	785.70	1253.22
7.	खनिज तेल-कच्चा तथा उत्पाद	4244.64	6273.52
8.	मोती, मूल्यवान तथा अर्द्ध मूल्यवान रत्न	2865.72	4241.53
9.	मशीनरी	5282.51	6979.82
10.	अपरिष्कृत रेशम	53.49	87.39
11.	सिंथैटिक तथा रिजनरेटेड फाइबर	37.37	69.47
12.	रंगाई, चर्मशोध तथा रंग सज्जा का सामान	94.60	146.00
13	औषधीय तथा भेषजीय उत्पाद	195.47	271.76
14.	धातु उत्पाद	193.23	271.06

स्रोत= डी जी आई एण्ड, कलकत्ता

बाढ़ नियंत्रण के उपाय

399. **श्री अनन्तराम जायसवाल:** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बाढ़ नियंत्रण संबंधी योजनाओं पर पहली पंचवर्षीय योजना से सातवीं पंचवर्षीय योजना तक कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(ख) क्या यह सच है कि इन योजनाओं पर भारी धनराशि खर्च करने के बावजूद भी इसका कोई स्थायी हल नहीं निकाला जा सका है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में देश के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों से परामर्श करके इसका कोई स्थायी हल निकालने का कभी प्रयास किया है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार उत्तर भारत में आने वाली बाढ़ और पठार में पानी की कमी संबंधी समस्याओं के स्थायी हल के लिए गंगा और कावेरी को जोड़ने के सुझाव पर विचार करेगी?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया): (क) लगभग 2,710 करोड़ रुपये।

(ख) गत 40 वर्षों के दौरान कुल 40 मिलियन हेक्टेयर बाढ़ प्रवण क्षेत्र में से लगभग 13.6 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को उचित सुरक्षा प्रदान की गई है।

(ग) राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (1976-80) का गठन बाढ़ नियंत्रण उपायों की सिफारिश करने के लिए किया गया है जिसमें प्रतिष्ठित इंजीनियर और वैज्ञानिक शामिल हैं। साथ ही इन बेसिनों में बाढ़ नियंत्रण की मास्टर योजना तैयार करने के लिए गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग और ब्रह्मपुत्र बोर्ड स्थापित किये गये हैं।

(घ) गंगा को कावेरी के साथ जोड़ने के प्रस्ताव पर सरकार द्वारा विचार किया गया और उसे तकनीकी रूप से अव्यवहार्य और आर्थिक रूप से निषेधात्मक पाया गया।

Strike by Bank Employees

400. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:
SHRIMATIMANORAMA PANDEY:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the bank employees all over the country observed one day's strike in June this year; and

(b) if so, what were their major demands and what action has been taken by Government in the matter?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI): (a) and (b) A section of officer employees of Public sector bank observed a day's strike on 12.6.1990 in support of their various demands such as lifting of ban on manpower growth in banks; stoppage of unilateral action of the Government/IBA in varying settled service conditions; alleged repressive acts of managements; etc. The grievances of